sprinkler system in soyabean and standardisation and evaluation of micro-irrigation methods for oilseed crops;

(b) if so, the details thereof during the last three years and the amount released to the states of U.P. and Haryana during that period; and

(c) if not, the reasons therefor and the future plans in that regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) Yes, Sir. Funds have been allocated under the Oilseed Production Programme covering oilseed crops including soyabean, for the distribution of sprinkler sets. The details of allocations for distribution of sprinkler sets, and amounts released to Uttar Pradesh and Haryana are as given below:

(Rs. in crore)

	1992-93	1993-94	1994-95
Allocation for distribution of sprinkler sets	4.15	10.88	16.17
Central assistance to U. P.	4.59	1.93	5.29
Allocation for sprinkler sets	0.24	0.35	0.51
Central assistance to Haryana	2.15	1.61	NIL*
Allocation for sprinkler sets	NIL	0.30	0.00

*The State of Haryana had unspent balances from previous years for utilisation during 1994-95.

An amount of Rs. 3.75 lakhs has been provided for the research project on standardisation and evaluation of micro irrigation methods for oilseed crops.

For the current financial year, the State Governments have been requested to indicate their proposals for distribution of sprinkler irrigation system on the basis of which central assistance will be provided to them.

Health Hazards in Prawn Farming

4034. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether complaints have been received regarding health hazard in and around prawn farming;

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard;

(c) if not, whether this will not affect the environment and result in pollution of surroundings; and

(d) the norms followed for the issue of licence in prawn farming?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) No, Sir. There is no hazard to the health of human or animal population in and around prawn farms.

(b) and (c) While there is no health hazard, there are reports of shrimp being affected by disease in the coastal districts of Andhra Pradesh and some coastal districts of Tamil Nadu. The State departments of fisheries are taking necessary steps to control the outbreak of disease and prevent its further spread. The Government of India have advised the States to ensure that shrimp farming is developed as an eco-friendly activity. In order to avoid pollution of the surroundings the

Government of Tamil Nadu have enacted legislation for regulation of prawn farming. The State Pollution Control Boards also examine proposals for prawn farms from the pollution angle.

(d) There is no requirement of licence for prawn farming by aquaculturists in India except the usual requirement of licence for Export Oriented Units under the regulations of the Ministry of Industry.

बासमती चावल का उत्पादन

4035. **प्रो० राम लखन सिंह वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में बासमती का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है ; और

(ग) विश्व व्यापार में इस वस्तु के संबंध में देश का हिस्सा कितना है तथा इसका प्रति क्विंटल निर्यात मूल्य कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) विभिन्न जिन्सों के उत्पादन के किस्म वार आकलन देश में नहीं रखे जा रहे हैं। फिर भी, मंडी आसूचना रिपोर्टों के अनुसार देश में सुपर-फाईन (बासमती सहित) चावल का उत्पादन लगभग 12.13 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में चावल के कुल उत्पादन का निर्यात प्रतिशत क्रमशः 9.91, 0.80, और 1.02 था।

(ग) 1992 के दौरान विश्व में चावल के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा 3.4 प्रतिशत था। 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए चावल का प्रति क्विन्टल मूल्य 1589 रुपये था।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का उत्पादन

4036. **प्रो. रामलखन सिंह वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ है और वर्ष 1994-95 के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ग) गत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान जिला-वार खाद्यान्नों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन क्रमशः 36.97 और 37.33 (संभावित) मिलियन मीटरी टन था। 1994-95 के लिए उत्तर प्रदेश के वास्ते खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 38.9 मिलियन मीटरी टन रखा गया था।

(ख) धान्य फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने "एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम–चावल (आई० सी० डी० पी०–चावल)" और "एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम–गेहूं (आई० सी० डी० पी०–गेहूं)" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करके उत्तर प्रदेश राज्य में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। ये योजनाएं इन दोनों फसलों में फसल प्रणाली क्षेत्रों पर आधारित है।

(ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए नवीनतम उपलब्ध जिला-वार खाद्यान्न उत्पादन के अनुमान संबंधी ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।